nt>

अध्यक्ष महोदय : प्रहलाद सिंह जी, आप शुरू कीजिए।

Title: Reported price scam in the name of levy on rice in Madhya Pradesh and other famine affected States.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं।

मैं भारत सरकार का ध्यान एक बहुत बड़े लेवी घोटाले की तरफ दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सन् 2000 से लेकर 2001-2002 में मैं जिस जिले से संसद सदस्य हूं, वहां पर धान का बहुत अधिक उत्पादन होता है। उसका एक पैमाना होता है, 2001 में वहां पर 5,57,366 मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ। 2002 में 4,45,869 मीट्रिक टन धान का उत्पादन हुआ। अध्यक्ष जी, सूखा पड़ा है, लेकिन वहां पर लेवी की मात्रा बढ़ती जा रही है। मैंने वहां के जिला कलैक्टर को भी लिखा है। धान का उत्पादन कम हुआ है, सूखे के बाद वहां पर लेवी की मात्रा बढ़ती गई है और जिन व्यापारियों के नाम का मैंने उल्लेख किया है, जिनकी मिलों में 100 क्विंवटल धान भी चावल बनाने लायक क्षमता नहीं है, उन्होंने 1-1 हजार क्विंटल की लेवी दी है, ऐसे प्रामाणिक तथ्य सामने आये हैं। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ सूखे के कारण धान का उत्पादन घटा है।

लेकिन लेवी की मात्रा में बढ़ोत्तरी कैसे हो गई। जिन उद्योगपतियों के पास धान से चावल बनाने की क्षमता एक हजार क्विंटल की थी, उन्हें दस हजार क्विंटल की लेवी कैसे दे दी। ऐसे प्रमाण होने के बावजूद भी वहां की राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं जिस जिले से आता हूं, मुझे आपका संरक्षण चाहिए, वहां पर साढ़े पांच लाख मीट्रिक टन तक धान पैदा होता है, लेकिन सूखे के बाद भी वहां दो-दो लाख क्विंटल की लेवी वसूल की गई है और किसानों को लाभ नहीं मिला। वहां पंजाब से चावल गया। यहां पर केन्द्रीय सरकार अपने मजदूरों के लिए जो धान खरीदती है, वह पालिश करके वहां दिया गया। मैं मांग करता हूं कि केन्द्रीय सरकार वहां एक टीम भेजे, जो इस घोटाले की जांच करे।